



Daily करेंट अफेयर्स

03 & 04 अगस्त 2025

NATIONAL AFFAIRS

1. MoTA ने देहरादून और भुवनेश्वर में आदि कर्मयोगी अभियान के तहत तीसरी और चौथी क्षेत्रीय प्रक्रिया प्रयोगशालाएँ शुरू कीं।



अगस्त 2025 में, जनजातीय मामलों के मंत्रालय (MoTA) ने भारत भर में जनजातीय शासन और क्षमता निर्माण को मजबूत करने के लिए देहरादून (उत्तराखंड) और भुवनेश्वर (ओडिशा) में आदि कर्मयोगी अभियान - राष्ट्रीय उत्तरदायी शासन मिशन के तहत तीसरे और चौथे क्षेत्रीय प्रक्रिया प्रयोगशाला (RPLs) का शुभारंभ किया।

- जनजातीय कार्य मंत्रालय की नई पहल का उद्देश्य पूरे भारत में 20 लाख आदिवासी कार्यकर्ताओं और स्थानीय परिवर्तन नेताओं के बीच एक मजबूत ज़मीनी नेतृत्व नेटवर्क तैयार करना है। इसमें 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UT) के 1 लाख से ज्यादा आदिवासी बहुल गाँवों, 3,000 ब्लॉकों और 550 ज़िलों तक पहुँच बनाकर समावेशी विकास और नीतिगत जवाबदेही को बढ़ावा देना शामिल होगा।

- क्षेत्रीय प्रक्रिया प्रयोगशालाएँ (RPLs), आदि कर्मयोगी अभियान के अंतर्गत जिला स्तर पर संचालित संस्थागत मंच हैं। ये प्रयोगशालाएँ क्षमता निर्माण और ज्ञान के आदान-प्रदान के प्रमुख केंद्रों के रूप में कार्य करती हैं। पहले दो RPLs पहले ही बेंगलुरु (कर्नाटक) और भोपाल (मध्य प्रदेश) में शुरू

किए जा चुके हैं, जो एक व्यापक राष्ट्रीय ढाँचे की नींव रखते हैं।

- देहरादून में शुरू किया गया तीसरा RPL पाँच राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, अर्थात् उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश (HP), जम्मू और कश्मीर (J&K) और उत्तर प्रदेश (UP) के राज्य मास्टर प्रशिक्षकों (SMTs) के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में कार्य करेगा। ये एसएमटी जिला मास्टर प्रशिक्षकों (DMTs) को प्रशिक्षित करके स्थानीय क्षमताओं का और निर्माण करेंगे, जिससे ज्ञान हस्तांतरण का एक व्यापक मॉडल तैयार होगा।

Key Points:-

(i) अगले चरण के तहत, देहरादून RPL में प्रशिक्षित SMTs अपने-अपने राज्यों में राज्य प्रक्रिया प्रयोगशालाएँ (SPLs) स्थापित करेंगे। ये SPLs जिला मास्टर प्रशिक्षकों (DMTs) के लिए प्रशिक्षण केंद्रों के रूप में कार्य करेंगे, जो आदिवासी समुदायों में जमीनी स्तर पर शासन सुधार रणनीतियों को लागू करने के लिए ज़िम्मेदार होंगे।

(ii) भुवनेश्वर में शुरू की गई चौथी RPL में झारखंड, बिहार और ओडिशा जैसे आदिवासी बहुल राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले 25 प्रतिभागियों का एक चयनित समूह शामिल है।

(iii) इस RPL को भारत ग्रामीण आजीविका फाउंडेशन (BRLF) द्वारा सुगम बनाया जा रहा है, जो रणनीतिक साझेदारी और ग्रामीण शासन नवाचार के माध्यम से सतत जनजातीय विकास को बढ़ावा देने में एक प्रमुख भागीदार है।

2. सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर ट्रक चालकों की सहायता के लिए 'अपना घर' विश्राम सुविधा शुरू की।



31 जुलाई 2025 को, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर 'अपना घर' (शाब्दिक अर्थ "हमारा घर") पहल शुरू की—जो भारत के राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर ट्रक चालकों के लिए स्वच्छ, सुरक्षित और किफायती विश्राम केंद्रों का एक नेटवर्क है। 1 जुलाई तक, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (OMCs) के माध्यम से खुदरा ईंधन आउटलेटों पर 4,611 बिस्तरों वाले कुल 368 विश्राम केंद्र चालू हो गए थे, जो सड़क सुरक्षा और चालक कल्याण को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

● प्रत्येक अपना घर में छात्रावास आवास (10 से 30 बिस्तरों तक), स्वच्छ शौचालय, समर्पित स्नान क्षेत्र (जिसे हौदा के रूप में जाना जाता है), शुद्ध पेयजल, स्वयं खाना पकाने का क्षेत्र और सुरक्षित वाहन पार्किंग के साथ-साथ पास में रेस्तरां या ढाबे उपलब्ध हैं।

● सुलभता और उपयोग में आसानी बढ़ाने के लिए विकसित एक समर्पित 'अपना घर' मोबाइल एप्लिकेशन, ट्रक ड्राइवरों को आस-पास की विश्राम सुविधाओं का पता लगाने, छात्रावासों में आवास पहले से बुक करने और सुविधाओं पर रीयल-टाइम फ्रीडबैक देने में सक्षम बनाता है। जून 2025 तक, इस ऐप को 65,000 से ज़्यादा पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के साथ व्यापक रूप से अपनाया गया, जो भारत के लंबी दूरी के ड्राइविंग समुदाय के

बीच इस पहल की बढ़ती लोकप्रियता और प्रासंगिकता को दर्शाता है।

● बुकिंग में पाँच गुना से भी ज़्यादा की वृद्धि हुई, जो अप्रैल-मई में लगभग 3,348 (55/दिन) से बढ़कर जून में 16,559 (552/दिन) हो गई। जून 2025 में, एक प्रमोशनल योजना शुरू की गई, जिसमें अपना घर आउटलेट्स से 50 लीटर हाई-स्पीड डीज़ल खरीदने वाले ड्राइवरों को मुफ्त डॉरमेट्री में ठहरने की सुविधा दी गई—जो तीन महीने तक चलेगी।

Key Points:-

(i) तेल विपणन कंपनियों ने अब तक 368 अपना घर सुविधाएँ स्थापित की हैं, जिनमें निर्माणाधीन दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर चार इकाइयाँ शामिल हैं, जिसके पूरा होने पर ऐसी 30 साइटें होंगी। सरकार का लक्ष्य मार्च 2027 तक एकीकृत ट्रक चालक सुविधाओं के साथ 1,000 बड़े प्रारूप वाले ईंधन खुदरा दुकानों का विस्तार करना है।

(ii) केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस बात पर ज़ोर दिया कि ज़्यादातर राजमार्ग दुर्घटनाएँ चालक की थकान और अपर्याप्त आराम के कारण होती हैं। इन वातानुकूलित सुविधाओं का उद्देश्य आराम और बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करके, चालकों की भलाई और सड़क सुरक्षा में सुधार करके ऐसे जोखिमों को कम करना है।

3. केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने उच्च शिक्षा में भेदभाव विरोधी दिशानिर्देशों को संशोधित करने के लिए विशेषज्ञ पैनल का गठन किया।



2 अगस्त को, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने उच्च शिक्षण संस्थानों में भेदभाव-विरोधी दिशानिर्देशों की समीक्षा और उन्हें मज़बूत बनाने के उद्देश्य से एक विशेषज्ञ पैनल का गठन किया। इस कदम का उद्देश्य अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), दिव्यांगजन (PwD) और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए समान वातावरण सुनिश्चित करना है।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के तहत इस पैनल का गठन किया गया है, जिसका उद्देश्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन और अल्पसंख्यकों सहित हाशिए पर रहने वाले समुदायों से संबंधित मौजूदा नियमों और योजनाओं की व्यापक समीक्षा करना है।

- यह पहल 6 जुलाई को जारी सुप्रीम कोर्ट के एक निर्देश के बाद की गई है, जिसमें प्रमुख संस्थानों में हाशिए के समुदायों के बीच भेदभाव और छात्रों की आत्महत्याओं पर चिंता जताई गई थी। कोर्ट ने परिसरों में इन संवेदनशील मुद्दों के समाधान के लिए "अलग सोच" की आवश्यकता पर ज़ोर दिया था।

- पैनल के अधिदेश में मौजूदा भेदभाव-विरोधी दिशानिर्देशों की प्रभावशीलता का आकलन करना शामिल है - जिसमें यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशन, 2012 और 2023 के अद्यतन शिकायत

निवारण मानदंड शामिल हैं - और कार्यान्वयन में अंतराल की पहचान करना शामिल है।

Key Points:-

(i) अपने निष्कर्षों के आधार पर, विशेषज्ञ पैनल परिसर के वातावरण को अधिक समावेशी बनाने, विविधता के बारे में जागरूकता बढ़ाने और भेदभावपूर्ण घटनाओं की रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित करने के लिए संशोधन और उपचारात्मक उपायों का प्रस्ताव करेगा।

(ii) मौजूदा UGS नियम संस्थानों को जाति, पंथ, धर्म, लिंग, विकलांगता या जातीयता के आधार पर किसी भी उत्पीड़न या उत्पीड़न को प्रतिबंधित करने, रोकने और दंडित करने का आदेश देते हैं, और भेदभाव को प्रभावी ढंग से दूर करने के लिए संपर्क अधिकारियों और शिकायत प्रकोष्ठों की आवश्यकता होती है।

(iii) इस पैनल का गठन हाशिए पर पड़े छात्रों के अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार के सक्रिय दृष्टिकोण को दर्शाता है और देश भर के परिसरों में समानता और सम्मान को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

4. भारत लगभग 8% वैश्विक हिस्सेदारी के साथ विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया है।



2023-24 में, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक बनकर उभरा, जिसकी कुल वैश्विक मछली उत्पादन में लगभग 8% हिस्सेदारी है। यह प्रभावशाली उपलब्धि अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि में हुई मज़बूत वृद्धि पर आधारित है, जो नीली क्रांति (नील क्रांति मिशन) और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) जैसी सरकारी पहलों से प्रेरित है। मत्स्य पालन क्षेत्र अब खाद्य सुरक्षा, निर्यात आय, ग्रामीण आजीविका और राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

● **भारत का मछली उत्पादन लगभग दोगुना हो गया है—2013-14 में 95.79 लाख टन से बढ़कर 2023-24 में 184.02 लाख टन हो गया, यानी 88.23 लाख टन की वृद्धि। इसमें अंतर्देशीय और जलीय कृषि उत्पादन में 77.71 लाख टन की वृद्धि हुई, जबकि समुद्री उत्पादन 5.02 लाख टन से बढ़कर 10.52 लाख टन हो गया।**

● **FAO की विश्व मत्स्य पालन और जलीय कृषि स्थिति (SOFIA) 2024 के अनुसार, भारत वैश्विक जलीय पशु उत्पादन में लगभग 8% का योगदान देता है, जो चीन के बाद दूसरे स्थान पर है, और अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन में विश्व स्तर पर अग्रणी है। यह क्षेत्र लगभग 3 करोड़ लोगों को रोजगार देता है, जिनमें से अधिकांश ग्रामीण और तटीय समुदायों में हैं, और राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 1.07% और कृषि सकल घरेलू उत्पाद या सकल मूल्य वर्धन (GVA) में 6.7% से अधिक का योगदान देता है।**

● **निर्यात में भी बढ़ोतरी हुई: 2023-24 में, भारत ने 17.81 लाख मीट्रिक टन समुद्री उत्पादों का निर्यात किया, जिससे लगभग ₹60,524 करोड़ की कमाई हुई, जो 2003-04 में ₹609.95 करोड़ से नाटकीय रूप से अधिक थी।**

Key Points:-

(i) इस वृद्धि को आधार देने वाली सरकारी योजनाओं में नीली क्रांति शामिल है, जिसे वित्त वर्ष 2015-16 में

3,000 करोड़ रुपये के प्रारंभिक आवंटन के साथ शुरू किया गया था, और PMMSY (2020-25), 20,050 करोड़ रुपये के वित्तपोषण वाला एक व्यापक मिशन है जिसका उद्देश्य मछली किसानों की आय को दोगुना करना, बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण करना और PM-MKSSY (प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना) के माध्यम से निर्यात को बढ़ावा देना है।

(ii) इन योजनाओं के तहत बुनियादी ढांचे के विकास में मत्स्य पालन और जलीय कृषि बुनियादी ढांचे विकास निधि (FIDF) (7,522 करोड़ रुपये स्वीकृत) के माध्यम से वित्त पोषण, एकीकृत एकापार्क का निर्माण (682.6 करोड़ रुपये में 11 स्वीकृत) और तटीय राज्यों में 291.37 करोड़ रुपये में 937 कृत्रिम चट्टानों की स्थापना शामिल है।

(iii) मत्स्य पालन में भारत के नेतृत्व को राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (NFDB) और केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान (CMFRI) जैसे संस्थानों का समर्थन प्राप्त है, जो डेटा संग्रह, स्टॉक आकलन, संसाधन मानचित्रण का समन्वय करते हैं और भारत के ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन एजेंडे के हिस्से के रूप में टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देते हैं।

5. भारत ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार घासस्थल पक्षी गणना की और 43 प्रजातियां दर्ज कीं।



18 मार्च और 25 मई 2025 के बीच, असम स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभयारण्य ने भारत की पहली समर्पित चरागाह पक्षी गणना की। पूर्वी असम, विश्वनाथ और नागांव वन्यजीव प्रभागों में 185 चरागाह स्थलों पर किए गए इस सर्वेक्षण में निष्क्रिय ध्वनिक निगरानी और बिंदु गणना सर्वेक्षण जैसे नवीन तरीकों का इस्तेमाल किया गया ताकि चरागाह पक्षी प्रजातियों का दस्तावेजीकरण किया जा सके, जिनका भारत के बाढ़ग्रस्त पारिस्थितिकी तंत्रों में बहुत कम अध्ययन किया जाता है।

- सर्वेक्षण में घास के मैदानों पर निर्भर पक्षियों की 43 प्रजातियों की पहचान की गई, जिनमें एक गंभीर रूप से लुप्तप्राय, दो लुप्तप्राय और छह संवेदनशील प्रजातियाँ शामिल हैं, जिन्हें IUCN की लाल सूची में वर्गीकृत किया गया है। यह काजीरंगा को घास के मैदानों में पक्षियों की विविधता के लिए भारत के शीर्ष आवासों में से एक बनाता है।

- दस प्राथमिकता वाली प्रजातियों पर विशेष जोर दिया गया जो वैश्विक स्तर पर संकटग्रस्त हैं या ब्रह्मपुत्र के बाढ़ के मैदानों में स्थानिक हैं: बंगाल फ्लोरिकन, स्वैम्प फ्रैंकोलिन, फिन्स वीवर, स्वैम्प ग्रास बैबलर, जेर्डॉन्स बैबलर, स्लेंडर-बिल्ड बैबलर, ब्लैक-ब्रेस्टेड पैरटबिल, मार्श बैबलर, ब्रिस्टल ग्रासबर्ड और इंडियन ग्रासबर्ड - सभी की पहचान जनगणना के दौरान की गई।

- एक प्रमुख आकर्षण लुप्तप्राय फिन्स वीवर (प्लोसियस मेगारिन्स), जिसे स्थानीय रूप से टुकुरा सोराई के नाम से जाना जाता है, की एक प्रजनन कॉलोनी की खोज थी। कोहोरा रेंज में 85 से ज्यादा घोंसले पाए गए, जो इसे एक ऐतिहासिक खोज और स्वस्थ चरागाह पारिस्थितिकी तंत्र का सूचक बनाता है।

Key Points:-

(i) इस गणना में पक्षियों की प्रजनन ऋतु के दौरान पक्षियों की आवाज़ें रिकॉर्ड करने के लिए ऊँचे घास के मैदानों में लगाए गए निष्क्रिय ध्वनिक रिकॉर्डर का इस्तेमाल किया गया। इन ध्वनि रिकॉर्डिंग का विश्लेषण बर्डनेट जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरणों का उपयोग करके किया गया, जिससे दूरदराज या दुर्गम इलाकों में भी पक्षियों की पहचान बिना किसी आक्रामक तरीके से की जा सकी।

(ii) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने "मन की बात" प्रसारण (जुलाई 2025) में, AI-संचालित कार्यप्रणाली के उपयोग की प्रशंसा की और बताया कि कैसे 40 से अधिक दुर्लभ घास के मैदानों में रहने वाली पक्षी प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास को नुकसान पहुंचाए बिना दर्ज किया गया, जो प्रौद्योगिकी और संरक्षण के सफल मिश्रण पर प्रकाश डालता है।

(iii) पर्यावरण मंत्री द्वारा 11 जुलाई 2025 को जारी की गई यह जनगणना रिपोर्ट दीर्घकालिक पारिस्थितिक निगरानी, अनुकूली आवास प्रबंधन और कम अध्ययन किए गए घास के मैदानों के पक्षी जीवन पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर जोर देती है। यह भविष्य में देश भर में घास के मैदानों के संरक्षण के प्रयासों के लिए एक रूपरेखा भी स्थापित करती है, और काजीरंगा के प्रसिद्ध विशाल जीवों के साथ-साथ पक्षी विविधता पर भी ध्यान केंद्रित करती है।

6. पश्चिम रेलवे ने मध्य प्रदेश में 155 साल पुरानी पातालपानी-कालाकुंड लाइन पर हेरिटेज ट्रेन फिर से शुरू की।



अस्थायी रोक के बाद, पश्चिम रेलवे ने अगस्त 2025 में मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक पातालपानी-कालाकुंड मीटर-गेज लाइन पर हेरिटेज ट्रेन का संचालन फिर से शुरू किया। डॉ. अंबेडकर नगर (पूर्व में महु)-खंडवा खंड का हिस्सा, यह 9.5 किमी लंबा खंड 1870 के दशक का है, जो इसे लगभग 155 साल पुराना बनाता है।

- 1870 के बाद के दशकों में निर्मित यह हेरिटेज लाइन, होलकर राज्य से ऋण लेकर शुरू की गई थी, जो इंदौर की राजधानी को खंडवा से जोड़ती थी। लगभग 9.5 किलोमीटर लंबे पातालपानी-कालाकुंड खंड में चार सुरंगें, 24 तीखे मोड़ और 41 पुल (छह बड़े और 35 छोटे) शामिल हैं। यह औपनिवेशिक काल की इंजीनियरिंग की एक उल्लेखनीय विरासत है।

- इस हेरिटेज सेवा की शुरुआत 25 दिसंबर 2018 को हुई थी, जब चुनौतीपूर्ण भू-भाग के कारण मीटर-गेज लाइन को ब्रॉड गेज में बदलने के बजाय संरक्षित किया गया था। अब दो ट्रेनें प्रतिदिन 5-10 किमी/घंटा की गति से इस मनोरम मार्ग पर चलती हैं, जहाँ से झरने, जंगली घाटियाँ और प्राकृतिक झरने दिखाई देते हैं।

Key Points:-

(i) जुलाई 2025 में, पर्यटकों की कम संख्या के कारण निलंबन की अवधि के बाद, पश्चिम रेलवे ने हेरिटेज परिचालन को पुनः शुरू किया, जिससे मध्य भारत में अभी भी चल रही सबसे पुरानी मीटर-गेज लाइन को पुनर्जीवित किया गया।

(ii) यह मार्ग भारतीय रेलवे की छह आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त हेरिटेज लाइनों में से एक है, हालाँकि अभी भी रेलवे बोर्ड से औपचारिक प्रमाणन की प्रतीक्षा है। पातालपानी-कालाकुंड हेरिटेज लाइन के रूप में अक्सर जाना जाने वाला यह मार्ग रेल प्रेमियों और पर्यटकों दोनों को समान रूप से आकर्षित करता है।

(iii) इस मार्ग का भू-भाग आमान परिवर्तन को अव्यावहारिक बनाता है। इसलिए, भारतीय रेलवे ने मीटर-गेज के इस विरासती हिस्से को संरक्षित करने का विकल्प चुना है, और ऐतिहासिक महत्व और मनोरम दृश्यों को बुनकर एक पुरानी यादों का एहसास कराया है।

7. VOC बंदरगाह भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला बंदरगाह बन गया है और उसने 1 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन को पार कर लिया है।



अगस्त 2025 में, तमिलनाडु के थूथुकुडी में स्थित वी.ओ. चिदंबरनार (VOC) बंदरगाह, सफलतापूर्वक हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने और 1 मेगावाट (MW) से अधिक रूफटॉप सौर ऊर्जा उत्पन्न करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह बन गया।

- इस उपलब्धि की घोषणा VOC पोर्ट के अध्यक्ष, IRSEE (भारतीय रेलवे विद्युत इंजीनियर्स सेवा) सुशांत कुमार पुरोहित ने सतत समुद्री विकास पर आयोजित एक ऐतिहासिक सम्मेलन के दौरान की।

- यह घोषणा भारतीय शिपिंग और बंदरगाह क्षेत्र में हरित पहल को बढ़ावा देने के लिए तमिलनाडु के थूथुकुडी में आयोजित 'ग्रीन पोर्ट्स एंड शिपिंग - चार्टरिंग सस्टेनेबल मैरीटाइम फ्यूचर' सम्मेलन में की गई।

- एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ((ii) सम्मेलन के प्रमुख सत्र समुद्री क्षेत्र में डीकार्बोनाइजेशन और हरित वित्तपोषण एवं नीतिगत ढांचे पर केंद्रित थे, जिनका उद्देश्य भारत के समुद्री उद्योग को शुद्ध-शून्य उत्सर्जन भविष्य की ओर अग्रसर करना था।) द्वारा अपने नाविक (भारतीय नक्षत्र के साथ नेविगेशन) सेल-3 के माध्यम से किया गया, जो हरित पहल और प्रदूषण नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है।

Key Points:-

(i) यह कार्यक्रम भारत समुद्री सप्ताह 2025 की अगुवाई में आयोजित की जा रही विषयगत कार्यशालाओं और रोड शो की राष्ट्रीय श्रृंखला का हिस्सा था, जो अक्टूबर 2025 में मुंबई, महाराष्ट्र में आयोजित किया जाना था।

(ii) सम्मेलन के प्रमुख सत्र समुद्री क्षेत्र में डीकार्बोनाइजेशन और हरित वित्तपोषण एवं नीतिगत ढांचे पर केंद्रित थे, जिनका उद्देश्य भारत के समुद्री उद्योग को शुद्ध-शून्य उत्सर्जन भविष्य की ओर

अग्रसर करना था।

BANKING & FINANCE

1. NPCI ने डिजिटल भुगतान को सुव्यवस्थित करने और नेटवर्क लोड को कम करने के लिए 1 अगस्त, 2025 से नए UPI दिशानिर्देश लागू किए हैं।



डिजिटल भुगतान की दक्षता और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI) प्रणाली के तहत नए दिशानिर्देश लागू किए हैं, जो 1 अगस्त, 2025 से प्रभावी होंगे। मई 2025 में जारी किए गए इन नियमों का उद्देश्य उपयोगकर्ता गतिविधि को स्ट्रीम करना, उपयोगकर्ता की गोपनीयता की सुरक्षा करना और UPI नेटवर्क पर डिजिटल भीड़ को कम करना है।

- NPCI ने गूगल पे (GPay), फोनपे और पेटीएम सहित सभी भुगतान सेवा प्रदाताओं (PSPs) को 31 जुलाई, 2025 तक नए UPI परिवर्तनों को लागू करने का निर्देश दिया है। इन पीएसपी को UPI पारिस्थितिकी तंत्र में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए संशोधित नीतियों का पालन करने हेतु अपने सिस्टम को अपग्रेड करना आवश्यक है।

- नए दिशानिर्देशों के तहत, बैलेंस पूछताछ की एक सीमा लागू की गई है, जिससे उपयोगकर्ताओं को मैन्युअल अनुरोधों के माध्यम से प्रति UPI एप्लिकेशन प्रतिदिन अधिकतम 50 बैलेंस जांच

करने की अनुमति मिल गई है। अनावश्यक सर्वर लोड को कम करने के लिए, एप्लिकेशन द्वारा ट्रिगर की जाने वाली किसी भी बैकग्राउंड या स्वचालित बैलेंस जांच की अब सख्त मनाही है।

Key Points:-

(i) एक और महत्वपूर्ण नियम खाता सूची तक पहुँच से संबंधित है। UPI एप्लिकेशन अब प्रति उपयोगकर्ता दिन में केवल 25 बार तक ही उपयोगकर्ताओं के लिंक किए गए बैंक खातों की जाँच और सूची बना सकते हैं, ताकि उपयोगकर्ता डेटा गोपनीयता को मज़बूत किया जा सके और तृतीय-पक्ष ऐप्स द्वारा बैंकिंग संसाधनों के अत्यधिक उपयोग को रोका जा सके।

(ii) दिशानिर्देश ऑटोपे लेनदेन के लिए एक नया नियम भी लागू करते हैं। सभी पीएसपी को उच्च-मांग अवधि के दौरान ट्राफ़िक की भीड़भाड़ को कम करने और पूरे सिस्टम में सुचारू लेनदेन प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए केवल गैर-व्यस्त घंटों के दौरान ही ऑटोपे निष्पादन निर्धारित करना होगा।

(iii) अंत में, अनुपालन न करने पर दंड का प्रावधान किया गया है। यदि कोई UPI एप्लिकेशन या PSP इन दिशानिर्देशों का पालन करने में विफल रहता है, तो उसे UPI APIs (एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस) तक सीमित पहुँच, नए उपयोगकर्ताओं के लिए ऑनबोर्डिंग सीमाएँ, और NPCI द्वारा लगाए गए तकनीकी या नियामक परिणामों का सामना करना पड़ सकता है।

2. इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने संपर्क रहित डिजिटल बैंकिंग के लिए आधार-आधारित चेहरा प्रमाणीकरण शुरू किया।



1 अगस्त 2025 को, संचार मंत्रालय, डाक विभाग के अधीन, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) ने देशव्यापी आधार-आधारित चेहरा प्रमाणीकरण सेवा शुरू की। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के सहयोग से विकसित इस नवाचार का उद्देश्य वृद्धों, दिव्यांगों और दूरदराज के ग्राहकों को एक सहज, सुरक्षित और सम्मानजनक बैंकिंग अनुभव प्रदान करना है।

• डाक विभाग के तहत सितंबर 2018 में स्थापित इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) देश भर में लगभग 1.65 लाख डाकघरों और 3 लाख डाक कर्मचारियों के कार्यबल के माध्यम से 11 करोड़ से अधिक ग्राहकों को सेवा प्रदान करता है - जो भारत की वंचित आबादी के दरवाजे तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाता है।

• UIDAI (UIDAI : भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) के ढांचे के तहत विकसित आधार-आधारित चेहरा प्रमाणीकरण सुविधा, उपयोगकर्ताओं को फिंगरप्रिंट स्कैन या वन-टाइम पासवर्ड (OTPs) के बजाय चेहरे की पहचान का उपयोग करके प्रमुख बैंकिंग सेवाएं - जैसे खाता खोलना, शेष राशि की जांच, फंड ट्रांसफर और उपयोगिता बिल भुगतान - करने में सक्षम बनाती है।

• IPPB के प्रबंध निदेशक और CEO आर. विश्वेश्वरन (भारतीय रेलवे सेवा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स - IRSEE) ने नवाचार की मानव-केंद्रित प्रकृति पर जोर

दिया, और कहा कि यह सुनिश्चित करता है कि घिसे हुए फिंगरप्रिंट या सीमित तकनीकी पहुंच के कारण पहुंच में कोई बाधा न आए, और यह IPPB के आदर्श वाक्य "आपका बैंक, आपके द्वार" के अनुरूप है।

Key Points:-

(i) यह संपर्क रहित, बायोमेट्रिक-मुक्त प्रमाणीकरण विधि विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांग व्यक्तियों या दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए फायदेमंद है, जो OTPs या फिंगरप्रिंट रीडर पर निर्भरता को खत्म करती है और स्वास्थ्य आपात स्थिति के दौरान स्वच्छता और पहुंच का समर्थन करती है।

(ii) यह रोलआउट भारत के व्यापक डिजिटल इंडिया और वित्तीय समावेशन मिशनों के अनुरूप है, जो डिजिटल विभाजन को पाटने और भारत के डाक नेटवर्क में कागज रहित, नकदी रहित, उपस्थिति रहित और अब स्पर्श रहित बैंकिंग प्रदान करने के IPPB के अधिदेश को सुदृढ़ करता है।

(iii) UIDAI के प्रमाणीकरण बुनियादी ढांचे के तहत मान्य उन्नत AI-संचालित चेहरे की पहचान एल्गोरिदम पर निर्मित, यह सुविधा IPPB मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर वास्तविक समय में पहचान को सुरक्षित रूप से सत्यापित कर सकती है, जिससे एक स्केलेबल, सुसंगत और मजबूत डिजिटल बैंकिंग अनुभव संभव हो सकता है।

3. RBI ने न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक के सारस्वत बैंक के साथ विलय को मंजूरी दी, जो 4 अगस्त 2025 से प्रभावी होगा।



भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मुंबई स्थित न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (NICBL) के देश के सबसे बड़े शहरी सहकारी ऋणदाता, सारस्वत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के साथ स्वैच्छिक विलय को मंजूरी दे दी है। यह एकीकरण 4 अगस्त 2025 से प्रभावी होगा, और सभी शाखाएं सारस्वत बैनर के तहत परिवर्तित हो जाएंगी।

● बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 44A (4) और धारा 56 के तहत स्वीकृत यह विलय सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण एकीकरण का प्रतीक है। जुलाई 2025 में शेयरधारकों की मंजूरी के बाद, विलय के बाद बनने वाली इकाई NICBL के ग्राहक आधार, परिसंपत्तियों और देनदारियों को पूरी तरह से अपने में समाहित कर लेगी और 4 अगस्त 2025 से NICBL की सभी 27 शाखाओं को सारस्वत बैंक के आउटलेट में बदल देगी।

● मुंबई मुख्यालय वाले सारस्वत सहकारी बैंक का मार्च 2025 तक कुल कारोबार लगभग ₹91,814 करोड़ था, जिसमें ₹55,481 करोड़ जमा और ₹36,333 करोड़ अग्रिम शामिल थे। यह आंकड़ा NICBL से कहीं ज़्यादा है, जिसका कुल कारोबार लगभग ₹3,560 करोड़ था, जिसमें ₹2,250-2,400 करोड़ जमा और ₹1,100-1,162 करोड़ अग्रिम शामिल थे।

Key Points:-

(i) वरिष्ठ अधिकारियों से जुड़े ₹122 करोड़ के गबन घोटाले के खुलासे के बाद, फरवरी 2025 में NICBL नियामकीय जाँच के दायरे में आ गया था। इसके बाद RBI ने बैंक पर रोक लगा दी, निकासी और ऋण देने के कार्यों पर रोक लगा दी, और बैंक के कामकाज की देखरेख के लिए एक प्रशासक नियुक्त कर दिया। इस विलय को जमाकर्ताओं की सुरक्षा और परिचालन स्थिरता बहाल करने के एक उपाय के रूप में देखा जा रहा है।

(ii) सारस्वत बैंक के अध्यक्ष गौतम ई. ठाकुर ने आश्वासन दोहराया कि ग्राहकों की जमा राशि और अर्जित ब्याज पूरी तरह से बरकरार रहेंगे और कोई कटौती नहीं की जाएगी। उन्होंने आगे बताया कि NICBL की ₹102.74 करोड़ की नकारात्मक निवल संपत्ति के बावजूद, सारस्वत बैंक का 17% से अधिक का मज़बूत पूँजी पर्याप्तता अनुपात और मज़बूत वित्तीय स्थिति उसे इस प्रभाव को झेलने में सक्षम बनाती है, और 12-24 महीनों में सुधार की उम्मीद है।

4. चॉइस AMC को चॉइस म्यूचुअल फंड ब्रांड के तहत म्यूचुअल फंड व्यवसाय शुरू करने के लिए सेबी की मंजूरी मिली।



1 अगस्त 2025 को, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (SEBI) ने चॉइस इंटरनेशनल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी चॉइस AMC प्राइवेट

लिमिटेड को अंतिम मंजूरी दे दी, जिससे इसे नव स्थापित चॉइस म्यूचुअल फंड के लिए एसेट मैनेजमेंट कंपनी (AMC) के रूप में काम करने के लिए अधिकृत किया गया, जिससे भारत के म्यूचुअल फंड उद्योग में इसका प्रवेश हुआ।

• मुंबई स्थित विविध वित्तीय सेवा समूह, चॉइस इंटरनेशनल लिमिटेड, अब आधिकारिक तौर पर म्यूचुअल फंड क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए तैयार है। यह समूह चॉइस म्यूचुअल फंड लॉन्च करेगा, जिसे चॉइस इंटरनेशनल द्वारा प्रायोजित किया जाएगा और इसकी AMC सहायक कंपनी के माध्यम से संचालित किया जाएगा। भारत के म्यूचुअल फंड मानदंडों के तहत, SEBI द्वारा इसकी पूरी नियामक निगरानी की जाएगी।

• नई AMC कम लागत वाले, पारदर्शी और स्केलेबल वित्तीय साधनों के पक्ष में वैश्विक रुझानों के अनुरूप, इंडेक्स फंड और एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ETFs) सहित निष्क्रिय निवेश उत्पादों के साथ परिचालन शुरू करने की योजना बना रही है। चरणबद्ध तरीके से इसकी शुरुआत का उद्देश्य भारत के वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र में खुदरा, उभरते हुए धनी और संस्थागत निवेशकों को आकर्षित करना है।

Key Points:-

(i) चॉइस इंटरनेशनल के CEO और कार्यकारी निदेशक अरुण पोद्दार ने ज़ोर देकर कहा कि यह मंजूरी समूह की वित्तीय सेवाओं के विस्तार में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। मैंने एक मज़बूत प्रशासन और नियामक ढाँचे के तहत पेशेवर रूप से प्रबंधित, तकनीक-संचालित उत्पाद पेश करने और निवेशकों का विश्वास बढ़ाने की महत्वाकांक्षा पर ज़ोर दिया है।

(ii) अब SEBI का लाइसेंस प्राप्त हो जाने के बाद, चॉइस AMC एक नामित ट्रस्टी कंपनी (म्यूचुअल फंड विनियमों के तहत अनिवार्य) के साथ मिलकर काम

करेगी और अपनी म्यूचुअल फंड योजनाओं को शुरू करने के लिए SEBI द्वारा निर्धारित सभी परिचालन शर्तों का पालन करेगी - जिसके दिवाली 2025 से पहले शुरू होने की उम्मीद है।

(iii) SEBI की यह मंजूरी भारत के म्यूचुअल फंड क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा को रेखांकित करती है। निष्क्रिय फंडों के माध्यम से प्रवेश करके, चॉइस AMC निवेश उत्पादों तक पहुँच को लोकतांत्रिक बनाने, बाज़ारों को मज़बूत करने और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के नियामक प्रयासों का समर्थन करने में अन्य उभरती हुई कंपनियों के साथ शामिल हो गई है।

ECONOMY & BUSINESS

1. GST परिषद ने 1 अक्टूबर, 2023 से ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ पर कुल जमा पर 28% कर की पुष्टि की।



2 अगस्त 2023 को, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में GST परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ पर 28% माल और सेवा कर (GST) लगाने के अपने निर्णय की पुष्टि की, जो 1 अक्टूबर 2023 से प्रभावी होगा, जो जीत के बजाय कुल खिलाड़ी जमा पर लागू होगा।

● अपनी 51वीं बैठक में, GST परिषद ने पुष्टि की कि कर की गणना दांव या जमा राशि के पूरे अंकित मूल्य पर की जाएगी—सकल गेमिंग राजस्व (GGR)

या प्लेटफ़ॉर्म शुल्क पर नहीं। यह कौशल के खेल और भाग्य के खेल, दोनों पर समान रूप से लागू होता है, जिससे राज्यों के वित्त मंत्रियों के बीच कर व्यवस्था को लेकर पहले की अस्पष्टता दूर हो गई है।

● CGST/IGST अधिनियमों के अंतर्गत एक अनुवर्ती विधि समिति ने सिफारिश की कि कर योग्य मूल्य में उपयोगकर्ताओं द्वारा प्लेटफ़ॉर्म पर जमा की गई कुल राशि शामिल हो—जिसमें वास्तविक या डिजिटल संपत्तियाँ शामिल हों। विदेशी प्लेटफ़ॉर्म के लिए GST पंजीकरण अनिवार्य करने और अनुपालन न करने पर पहुँच को अवरुद्ध करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियमों को सशक्त बनाने के उपाय भी प्रस्तावित किए गए।

● संशोधनों के लागू होने के बाद से, ऑनलाइन गेमिंग से मासिक जीएसटी संग्रह में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है—लगभग ₹250 करोड़ से बढ़कर ₹1,100 करोड़ हो गया, यानी 412% की वृद्धि। हालाँकि, इस क्षेत्र में राजस्व में 20-30% की गिरावट और लाभ मार्जिन में 60-70% की कमी देखी गई, जिससे विशेष रूप से स्टार्ट-अप और SMEs के लिए काफी संकट पैदा हो गया।

Key Points:-

(i) ड्रीम11 और गेम्सक्राफ्ट जैसे उद्योग के नामों सहित 27 से अधिक गेमिंग कंपनियाँ, अधिकारियों द्वारा रखी गई 1.12 लाख करोड़ रुपये से अधिक की पूर्वव्यापी GST मांगों का विरोध कर रही हैं।

(ii) उनका तर्क है कि कौशल वाले खेलों को कानूनी तौर पर जुए से लंबे समय से अलग माना जाता रहा है और उन पर समान शुल्क नहीं लगाना चाहिए। यह विवाद अब सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है।

(iii) परिषद इस 28% कर व्यवस्था के प्रभाव की समीक्षा लागू होने के छह महीने बाद, यानी अप्रैल 2024 के आसपास, राज्य-विशिष्ट चिंताओं और संभावित उद्योग राहत पर विचार करते हुए करेगी। गोवा, कर्नाटक और सिक्किम जैसे राज्यों द्वारा भारी

बोझ के बारे में चेतावनियों के बावजूद, राजस्व और नियामकीय स्थिरता का हवाला देते हुए, इस कर को बरकरार रखने पर समग्र सहमति बनी हुई है।

2. Fitch रेटिंग्स ने निर्यात में कमजोरी और वैश्विक अनिश्चितता का हवाला देते हुए वित्त वर्ष 26 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान घटाकर 6.3% कर दिया।



अगस्त 2025 में, एक प्रमुख अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, फिच रेटिंग्स इंक. ने मध्यम निर्यात मांग और अमेरिकी टैरिफ के सीमित प्रभाव का हवाला देते हुए, वित्त वर्ष 26 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वृद्धि दर के अनुमान को संशोधित कर 6.3% कर दिया। इस अद्यतन अनुमान का विवरण फिच की नवीनतम रिपोर्ट "इंडिया कॉरपोरेट्स क्रेडिट ट्रेंड्स: जुलाई 2025" में दिया गया है।

● Fitch के नीचे की ओर संशोधन से वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर 6.3% हो गई है, जो अप्रैल 2025 में जारी वैश्विक आर्थिक आउटलुक (GEO) रिपोर्ट में जारी 6.4% के पहले के अनुमान से कम है। एजेंसी ने इस नरमी के पीछे प्राथमिक कारणों के रूप में व्यापक आर्थिक दबाव और कमजोर वैश्विक व्यापार का हवाला दिया।

● रिपोर्ट के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) द्वारा भारतीय कॉर्पोरेट निर्यात पर हाल ही में लगाए गए 25% टैरिफ का सीधा प्रभाव सीमित रहा है, जिसका मुख्य कारण अमेरिकी बाज़ार में भारत का कम निर्यात जोखिम है। भारतीय कंपनियाँ, विशेष रूप से विनिर्माण और प्रमुख क्षेत्रों में, घरेलू मांग पर अधिक निर्भर रही हैं, जिसने उन्हें बाहरी झटकों से बचाया है।

Key Points:-

(i) रिपोर्ट में घरेलू बुनियादी ढाँचे पर खर्च में वृद्धि पर भी प्रकाश डाला गया है, जिससे इस्पात, सीमेंट और बिजली जैसे प्रमुख क्षेत्रों में मांग में वृद्धि हुई है। हालाँकि, फिच ने कमजोर वैश्विक उपभोग प्रवृत्तियों और बढ़ती ब्याज लागत का हवाला देते हुए वित्त वर्ष 26 में भारतीय कंपनियों के कुल राजस्व में 3% की गिरावट की चेतावनी दी है।

(ii) एक संबंधित अपडेट में, S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस (MI) ने भी वित्त वर्ष 26 के लिए भारत की GDP 6.2% रहने का अनुमान लगाया है, जो वित्त वर्ष 25 में 6.5% से कम है, बशर्ते अमेरिकी टैरिफ सितंबर 2025 के बाद भी लागू रहें।

(iii) S&P ने इस अपेक्षित मंदी का कारण लगातार बाहरी प्रतिकूल परिस्थितियों और भारतीय कंपनियों पर घरेलू लागत दबाव को बताया।

AWARDS

1. मैग्नस कार्लसन को रियाद में पहली बार आयोजित शतरंज ईस्पोर्ट्स विश्व कप में चैंपियन का ताज पहनाया गया।



1 अगस्त 2025 को, नॉर्वे के ग्रैंडमास्टर मैग्नस कार्लसन ने सऊदी अरब के रियाद में आयोजित पहले शतरंज ईस्पोर्ट्स विश्व कप का खिताब फ्रांस के अलीरेज़ा फ़िरौज़ा को सीधे सेटों में हराकर जीता। ईस्पोर्ट्स विश्व कप फ्रैंचाइज़ी के तहत आयोजित इस प्रतियोगिता में 1.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की पुरस्कार राशि थी, जिसमें कार्लसन ने 250,000 अमेरिकी डॉलर जीते।

- कार्लसन की जीत ने ईस्पोर्ट्स वर्ल्ड कप फाउंडेशन द्वारा प्रबंधित 2025 ईस्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में शतरंज को एक प्रमुख ईस्पोर्ट्स खेल के रूप में स्थापित कर दिया। 16 खिलाड़ियों वाला यह आयोजन—जिसमें चैंपियंस शतरंज टूर के माध्यम से प्रतिभागियों को योग्य बनाया गया—29 जुलाई से 1 अगस्त 2025 तक Chess.com प्लेटफॉर्म पर आयोजित किया गया, जिसने डिजिटल शतरंज प्रतियोगिता के विकास की ओर वैश्विक ध्यान आकर्षित किया।

- ग्रैंड फ़ाइनल में, कार्लसन (टीम लिक्विड का प्रतिनिधित्व करते हुए) ने टीम फाल्कन्स के फ़िरौज़ा को निर्णायक रूप से हराया, लगातार दो बेस्ट-ऑफ़-थ्री सेट जीते, प्रत्येक 3-1 के स्कोर से। इस जीत के साथ टीम लिक्विड ने क्लब चैंपियनशिप की समग्र तालिका में बढ़त हासिल कर ली।

Key Points:-

इससे पहले, टूर्नामेंट में, हिकारू नाकामुरा

सेमीफाइनल में पहुँचे, लेकिन कार्लसन से 4-3 के आर्मगेडन टाईब्रेक में कांटे की टक्कर में हार गए। नाकामुरा ने बाद में कांस्य पदक के मुकाबले में जनरल जी ईस्पोर्ट्स के अर्जुन एरिगैसी को 3.5-2.5 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया और 145,000 अमेरिकी डॉलर की राशि अर्जित की।

(ii) अपने स्वीकृति भाषण में, कार्लसन ने इस आयोजन को "एक नई ज़मीन पर विजय" कहा और आशा व्यक्त की कि शतरंज भविष्य की ई-स्पोर्ट्स प्रतियोगिताओं का एक स्थायी हिस्सा बन जाएगा। शतरंज के इस आयोजन में शामिल होने से दर्शकों की संख्या में भारी वृद्धि हुई—30,000 से ज़्यादा दर्शकों ने Chess.com पर लाइव देखा, जिसने ई-स्पोर्ट्स के क्षेत्र में ग्रैंडमास्टर मैचों के नए रिकॉर्ड स्थापित किए।

(iii) यह ऐतिहासिक जीत न केवल कार्लसन के लिए एक व्यक्तिगत उपलब्धि थी, बल्कि एक डिजिटल खेल के रूप में शतरंज के लिए एक बड़ी छलांग भी थी। उनकी यह जीत पारंपरिक बोर्ड गेम्स और ई-स्पोर्ट्स के विलय को रेखांकित करती है, जो वैश्विक खेल मनोरंजन में व्यापक रुझानों को दर्शाती है।

App and Web Portal

1. असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने 1 करोड़ पौधे लगाने के अभियान को प्रोत्साहित करने के लिए 'अमृतवृक्ष आंदोलन' ऐप लॉन्च किया।



2 अगस्त 2023 को, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने 'अमृत वृक्षारोपण आंदोलन' मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल का अनावरण किया, जिससे राज्य के महत्वाकांक्षी वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत हुई। इस पहल का उद्देश्य 17 सितंबर 2023 को एक ही दिन में पूरे असम में सागौन, साल और चंदन जैसे 1 करोड़ व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य पौधे लगाना है, जिसमें राज्य के हरित क्षेत्र को मज़बूत करने और जलवायु परिवर्तन में योगदान देने के लिए जनभागीदारी शामिल है।

- गुवाहाटी के जनता भवन में लॉन्च किया गया अमृतवृक्ष आंदोलन मोबाइल ऐप और पोर्टल, प्रतिभागियों को पंजीकृत करने, जियो-टैग्ड पौधरोपण तस्वीरें साझा करने और भागीदारी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के रूप में काम करता है। पंजीकृत नागरिकों को प्रति पौधा ₹100 मिलते हैं, और अगर पौधा तीन साल तक जीवित रहता है तो ₹200 अतिरिक्त मिलते हैं।

- 17 सितंबर 2023 को, असम भर में महिला स्वयं सहायता समूहों की लगभग 40 लाख सदस्यों को दो-दो पौधे लगाने के लिए पंक्तिबद्ध किया गया था, जो कुल 80 लाख थे, जबकि शेष 20 लाख से अधिक पौधे सरकारी अधिकारियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं, चाय बागान श्रमिकों और आम जनता द्वारा लगाए जाने थे।

- इस अभियान का लक्ष्य न केवल पर्यावरण संरक्षण है, बल्कि ग्रामीण आजीविका में भी सुधार लाना है। लगाए गए पौधों को वन विभाग की अनुमति के बिना व्यावसायिक रूप से बेचा जा सकता है, जिससे किसानों और ग्रामीणों को आय के अवसर मिलेंगे।

Key Points:-

(i) असम का लक्ष्य भविष्य के चरणों में इस अभियान का विस्तार करना है—2024 में 3 करोड़ और 2025 तक 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य, जिसका लक्ष्य राज्य में वन क्षेत्र को 36% से बढ़ाकर 38% करना है। 2024 के संस्करण में डिजिटल उन्नयन की शुरुआत की गई, जिससे ऐप के माध्यम से पंजीकरण और निगरानी आसान हो गई।

(ii) असम की हरित अर्थव्यवस्था रणनीति और जलवायु लचीलापन एजेंडे का एक प्रमुख तत्व बताई गई यह पहल, मुख्यमंत्री सरमा के सतत विकास और जैव विविधता संवर्धन के दृष्टिकोण के अनुरूप है, और इसे राष्ट्रीय जलवायु लक्ष्यों में असम के योगदान के रूप में प्रचारित किया गया है।

SCIENCE AND TECHNOLOGY

1. स्पेसएक्स ने NASA के वाणिज्यिक कू कार्यक्रम के तहत कू-11 अंतर्राष्ट्रीय कू को ISS के लिए प्रक्षेपित किया।



1 अगस्त 2025 को, स्पेसएक्स ने NASA के कमर्शियल कू प्रोग्राम के तहत अपने कू-11 मिशन को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर के लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A से फाल्कन9 रॉकेट और कू ड्रैगन एंडेवर कैप्सूल के ज़रिए सफलतापूर्वक लॉन्च किया। यह मिशन चार अंतरिक्ष यात्रियों को छह महीने के नियोजित प्रवास के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ले जाएगा।

● अंतर्राष्ट्रीय कू-11 मिशन में NASA के अंतरिक्ष यात्री ज़ेना कार्डमैन (कमांडर) और माइक फिन्के (पायलट), जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी (JAXA) से किमिया यूई और रोस्कोस्मोस का प्रतिनिधित्व करने वाले रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग प्लाटोनोव शामिल हैं। यह NASA के वाणिज्यिक कू कार्यक्रम के तहत ग्यारहवीं कू रोटेशन उड़ान और ड्रैगन वाहनों के लिए बारहवीं मानव अंतरिक्ष उड़ान है।

● मूल रूप से 31 जुलाई 2025 को दोपहर 12:09 बजे पूर्वी मानक समय (EDT) पर निर्धारित प्रक्षेपण, क्यूम्यलस बादलों के कारण स्थगित कर दिया गया था। स्पेसएक्स ने कड़े प्रक्षेपण सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, मौसम की स्थिति ठीक होने पर प्रक्षेपण को 1 अगस्त 2025 को सुबह 11:43 बजे पूर्वी मानक समय (EDT) पर पुनर्निर्धारित किया।

● सफल चरण पृथक्करण के बाद, फाल्कन9 प्रथम-चरण बूस्टर (B1094.3) केप कैनावेरल स्पेस फ़ोर्स स्टेशन के लैंडिंग ज़ोन 1 पर स्वचालित रूप से उतरा, जो इसके तीसरे मिशन पुनः उपयोग को चिह्नित करता है। ड्रैगन कैप्सूल 2 अगस्त 2025 को लगभग 3 बजे सुबह EDT (7:00 UTC) पर हार्मनी मॉड्यूल के जेनिथ पोर्ट पर ISS के साथ स्वचालित रूप से डॉक किया गया।

Key Points:-

(i) यह माइक Fincke की अंतरिक्ष में वापसी का प्रतीक है, जो अंतरिक्ष शटल एंडेवर STS -134 पर अपनी आखिरी उड़ान के बाद 14 साल के अंतराल

के बाद अंतरिक्ष में वापस लौटे हैं। ज़ेना कार्डमैन और ओलेग प्लाटोनोव के लिए, यह उनका पहला अंतरिक्ष मिशन है; किमिया यूई अपनी दूसरी यात्रा पर हैं, जापानी अंतरिक्ष यात्री इससे पहले 2015 में उड़ान भर चुकी हैं।

(ii) यह मिशन NASA के आर्टेमिस कार्यक्रम के विज्ञान और वैश्विक अंतरिक्ष सहयोग के अनुरूप है, जिसमें NASA, रोस्कोस्मोस और जाक्सा के प्रयासों को एक निजी क्षेत्र के अंतरिक्ष यान के माध्यम से एकीकृत किया गया है। कू-11, एक्सपेडिशन 73 के चालक दल के साथ वैज्ञानिक अनुसंधान और स्टेशन रखरखाव में सहायता करेगा, और उसके बाद कू-10 के प्रस्थान करने वाले सदस्यों से कार्यभार संभालेगा।

(iii) अमेरिकी प्रशासन द्वारा वित्त वर्ष 2026 के लिए आई.एस.एस. संचालन कार्यक्रमों सहित नासा के लिए प्रस्तावित वित्त पोषण में कटौती के बाद, बजट की कमी और रूसी सहयोग के साथ तालमेल के बीच समय-निर्धारण को अनुकूलित करने के लिए NASA कू-11 मिशन की सामान्य छह महीने की अवधि को बढ़ाकर आठ महीने कर सकता है।

Static GK

Ministry of Tribal Affairs (MoTA)	केंद्रीय मंत्री: जुएल ओराम	मुख्यालय: नई दिल्ली
Assam	मुख्यमंत्री: हिमंत बिस्वा सरमा	राज्यपाल: लक्ष्मण आचार्य
Madhya Pradesh	राजधानी: भोपाल	राज्यपाल: मंगूभाई सी. पटेल
National Payments Corporation of India (NPCI)	MD & CEO : दिलीप अस्बे	मुख्यालय: मुंबई
Fitch Ratings	अध्यक्ष : इयान लिनेल	मुख्यालय : न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका (USA)
SpaceX	CEO : एलोन मस्क	मुख्यालय : कैलिफ़ोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका (USA)